

जिस्टड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 7 मार्च, 1996/17 फाल्गुन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 7 मार्च, 1996

संख्या 1-29/96-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 14)

जो दिनांक 7 मार्च, 1996 को हिमचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

सचिव।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में, व्यवसाय बन्द किए जाने पर, अधिवक्ताओं के फायदे के लिए, कल्याण निधि के गठन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुपंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 है ।

संक्षिप्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं

(क) "अधिवक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन तैयार की गई और रखी गई राज्य अधिवक्ता नामावली में दर्ज किया गया है और वह किसी विधिज्ञ संगम का सदस्य है ;

(ख) "विधिज्ञ संगम" से विधिज्ञ परिषद् द्वारा धारा 14 के अधीन मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता संगम अभिप्रेत है ;

(ग) "विधिज्ञ परिषद्" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "व्यवसाय बन्द करना" से विधिज्ञ परिषद् द्वारा रखी गई राज्य नामावली से किसी अधिवक्ता का नाम उसकी मृत्यु या निवृत्ति के कारण अथवा स्थायी शारीरिक या मानसिक निःशक्तता के आधार पर, उसके स्वेच्छा से व्यवसाय बन्द करने के कारण, हटाना अभिप्रेत है ;

(ङ) "आश्रित" से निधि के सदस्य पर आश्रित का पति या पत्नी, माता-पिता और बच्चे अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत हैं उसकी विधवा पुत्री और व्यस्क बच्चे जो शारीरिक निःशक्तता या उन्मत्तता से ग्रस्त हैं और उस द्वारा पोषित हैं या उनमें से ऐसे जो उसकी मृत्यु पर जीवित रहते हैं ;

(च) "निधि" से धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(छ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "निधि सदस्य" से ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है जिसे निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका सदस्य बना रहता है ;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1961 का 25

1961 का 25

- (अ) "निवृत्ति" से विधिज्ञ परिषद् को संसूचित और उसके द्वारा अभिलिखित अधिवक्ता के रूप में, व्यवसाय बन्द करना अभिप्रेत है ;
- (ट) "टिकट" से धारा 26 के अधीन मुद्रित और वितरित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट अभिप्रेत है ;
- (ठ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;
- (ड) "व्यवसाय का निलम्बन" से अधिवक्ता के रूप में स्वेच्छा से व्यवसाय का निलम्बन या विधिज्ञ परिषद् द्वारा अवचार के लिए निलम्बन अभिप्रेत है ;
- (ढ) "न्यासी समिति" से धारा 4 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति अभिप्रेत है ;
- (ण) "वकालतनामा" के अन्तर्गत उपसंज्ञाति ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज है जिस द्वारा कोई अधिवक्ता किसी न्यायालय, अधिकरण या जो किसी अन्य विधि द्वारा साक्ष्य लेने या किसी विवाद का न्याय-निर्णयन या विनिश्चय करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत संस्था अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने या अभिवचन करने के लिए सशक्त है ।

अधिवक्ता
कल्याण
निधि ।

3. (1) सरकार, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी ।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

- (क) दस हजार रुपये की आरम्भिक रकम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो इस के गठन के समय विधिज्ञ परिषद् जमा करे ;
- (ख) धारा 13 के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा संदत्त रकम ;
- (ग) कोई अतिरिक्त अभिदाय जो विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया जाए ;
- (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, किसी विधिज्ञ संगम, किसी अधिवक्ता संगम या अन्य संगम अथवा संस्था या किसी अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा निधि में किया गया कोई स्वेच्छिक दान या अभिदाय ;
- (ङ) धारा 11 के अधीन उधार ली गई कोई राशि ;
- (च) धारा 17 के अधीन संगृहीत सभी राशियां ;
- (छ) समूह बीमा पालिसी के अधीन निधि के सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त सभी राशियां ;
- (ज) निधि के सदस्यों की समूह बीमा पालिसियों के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश या प्रतिदाय ;
- (झ) निधि के किसी भाग के किसी विनिधान पर कोई ब्याज या लाभांश अथवा अन्य प्रत्यागम ;
- (ञ) धारा 27 के अधीन टिकटों के विक्रय द्वारा संगृहीत सभी राशियां,
- (3) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियां ऐसे अभिकरणों को या द्वारा ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति में संदत्त या संगृहीत की जाएंगी और निधि के लेखे ऐसी रीति में रखे जाएंगे, जैसी विहित की जाए ।

4. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख में जो उसमें न्यासी समिति विनिर्दिष्ट की जाए, "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति" के नाम का गठन। से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी।

(2) न्यासी समिति पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) न्यासी समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—

(क) हिमाचल प्रदेश विधि परिषद् का अध्यक्ष जो न्यासी समिति का अध्यक्ष होगा, पदेन ;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य का महाधिवक्ता, पदेन सदस्य ;

(ग) सरकार के विधि विभाग का सचिव, पदेन सदस्य ;

(घ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य ;

(ङ) विधि परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट इसके तीन सदस्य ; और

(च) विधि परिषद् का सचिव जो न्यासी समिति का सचिव होगा, पदेन।

(4) उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन सरकार द्वारा और खण्ड (ङ) के अधीन विधि परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक या उप-धारा 3 के खण्ड (ङ) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की दशा में विधि परिषद् में उसकी सदस्यता की कालावधि तक, जो भी कम हो, या ऐसे सदस्य द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने और उसके त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने तक, पद धारण करेगा।

5. (1) कोई व्यक्ति, धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन न्यासी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निरहित होगा, यदि वह—

(क) विकृतचित हो जाता है ; या

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया है ; या

(ग) न्यासी समिति की अनुमति के बिना न्यासी समिति की तीन से अधिक लगातार बैठकों से अनुपस्थित है :

परन्तु इस खण्ड के अधीन जो सदस्य पद पर नहीं रहता है उसे न्यासी समिति द्वारा ऐसे सदस्य के रूप में बने रहना अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि ऐसा सदस्य अनुपस्थिति की माफी के लिए आवेदन करता है ; या

(घ) निधि का व्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) ; या

(ङ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी दांडिक न्यायालय

न्यासी समिति के नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और हटाया जाना।

द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि अपास्त नहीं कर दी गई हो; या

(च) विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होते हुए—

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करना बन्द कर देता है ; या

1961 का

25

(ii) विधिज्ञ परिषद् का सदस्य नहीं रहता है ; या

(iii) वृत्तिक अवचार के आधार पर व्यवसाय करने से विवर्जित है ।

(2) सरकार किसी सदस्य को, जो उप-धारा (1) के अधीन निरहित है या हो गया है, न्यासी समिति की सदस्यता से हटा सकेगी :

परन्तु विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को हटाए जाने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक सदस्य और विधिज्ञ परिषद् को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

न्यासी समिति

के नाम-

निर्दिष्ट सद-

स्यों द्वारा

त्यागपत्र

और आक-

स्मिक रिक्ति-

तयों का

भरा जाना ।

6. (1) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, यथास्थिति, सरकार या विधिज्ञ परिषद् को लिखित रूप में तीन मास का नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा और, यथास्थिति, सरकार या विधिज्ञ परिषद् द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(2) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य के पद में मृत्यु, त्यागपत्र या धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्य को हटाए जाने के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, सरकार या विधिज्ञ परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करके यथाशीघ्र सुविधानुसार, भरी जा सकेगी और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उस सदस्य की अवधि के शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया जाता है ।

रिक्ति, लुटि

आदि द्वारा

न्यासी समिति

के कार्यों

का अविधि-

मान्य न

होना ।

7. न्यासी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्यवाही, मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) समिति में किसी रिक्ति या गटन में लुटि ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई लुटि या अनियमितता ; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली कोई लुटि या अनियमितता ।

निधि का

निहित करना

और उप-

योजन ।

8. निधि न्यासी समिति में निहित होगी और उस द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उसके प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी ।

9. (1) न्यासी समिति, निधि का प्रबन्ध करेगी।

न्यासी समिति
के कृत्य।

(2) निधि का प्रबन्ध करने में, न्यासी समिति इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,—

- (क) न्यास में निधि से सम्बन्धित रकमों और आस्तियों को धारित करेगी ;
- (ख) निधि में प्रवेश या पुनःप्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और उनकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे आवेदनों का निपटारा करेगी ;
- (ग) निधि में सौं संचाय करने के लिए, यथास्थिति, निधि के सदस्यों, उनके नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों से आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों का निपटारा करने के लिए ऐसी जांच करेगी जो वह आवश्यक समझे तथा उनकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर आवेदनों का निपटारा करेगी ;
- (घ) आवेदनों पर इसके विनिश्चय न्यासी समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगी ;
- (ङ) आवेदकों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रकमें संदत्त करेगी ;
- (च) सरकार और विधिज्ञ परिषद् को ऐसी कालिक और वार्षिक रिपोर्टें भेजेगी, जैसी विहित की जाएं ;
- (छ) निधि में प्रवेश या पुनःप्रवेश या निधि के फायदे के दावों के लिए आवेदनों के बारे में न्यासी समिति के विनिश्चय डाक प्रमाणित डाक द्वारा आवेदकों को संसूचित करेगी ;
- (ज) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अधिकारी और सेवकों को जो यह आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाएं, नियुक्त करेगी ; और
- (झ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस द्वारा किए जाने अपेक्षित हैं या किए जाएं।

10. विधिज्ञ परिषद् या न्यासी समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ता संगम या विधिज्ञ संगम को [ऐसे निदेश, जो इसकी राय में आवश्यक या समीचीन हैं दे सकेगी।

निदेश देने
की शक्ति

11. (1) न्यासी समिति, सरकार और विधिज्ञ परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगी।

निधियां,
उधार लेना
और
विनिष्ठा न

(2) न्यासी समिति, निधि की भागरूप समस्त धनराशियां और प्राप्तियां किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी या उसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गई किन्हीं युनिटों में अथवा किसी डाकघर द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्रों या केन्द्रीय

सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियन्त्रणाधीन निगम द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली प्रतिभूतियों या ऋणों में अथवा किसी अन्य रीति में, जैसा विधिज्ञ परिषद्, समय-समय पर, सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेश दे, विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन शोध और संदेय सभी रकमों और निधि के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बन्धित सभी व्यय निधि में से संदत्त किए जाएंगे।

(4) न्यासी समिति के लेखे की वार्षिक संपरीक्षा विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाएगी।

(5) संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित न्यासी समिति के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ न्यासी समिति द्वारा विधिज्ञ परिषद् और सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और विधिज्ञ परिषद् उस के बारे में न्यासी समिति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(6) न्यासी समिति, उप-धारा (5) के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करेगी।

सचिव की
शक्तियां
और कर्तव्य।

12. न्यासी समिति का सचिव—

- (क) न्यासी समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा और इसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (ख) न्यासी समिति के लिए और उसके विरुद्ध सभी वादों और कार्यवाहियों में न्यासी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा ;
- (ग) न्यासी समिति के सभी विनिश्चयों और अनुदेशों को अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करेगा ;
- (घ) अध्यक्ष या उसके नामनिर्देशितों के साथ संयुक्त रूप से न्यासी समिति के बैंक खाते चलाएगा ;
- (ङ) न्यासी समिति की बैठकें बुलाएगा और उनके कार्यवृत्त तैयार करेगा ;
- (च) समस्त आवश्यक अभिलेखों और सूचना सहित न्यासी समिति की बैठक में हाजिर होगा ;
- (छ) ऐसे प्रारूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख रखेगा जो समय-समय पर विहित किए जाएं और न्यासी समिति से सम्बन्धित सभी पत्र व्यवहार करेगा ;
- (ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यासी समिति द्वारा संव्यवहारित कारबार का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ;
- (झ) टिकटों के विक्रय और उससे सम्बद्ध अन्य विषयों के सम्बन्ध में विधिज्ञ संगम के लेखे और रजिस्ट्रों का कालिकत निरीक्षण और सत्यापन करेगा ;
- (ञ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो न्यासी समिति और विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

13. विधिज्ञ परिषद्, इस द्वारा वसूल की गई नामांकन फीस के दस प्रतिशत के बराबर रकम प्रतिवर्ष निधि में संदत्त करेगी ।

कुछ धन का निधि में अन्तरण ।

14. (1) राज्य के किसी भी भाग में कार्य कर रहे किसी भी नाम से ज्ञात सभी अधिवक्ता संगम, इस निमित्त विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से पूर्व या ऐसी बढ़ाई गई तारीख से पूर्व जैसी अधिसूचित की जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के लिए विधिज्ञ परिषद् को, आवेदन करेगा । इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् बनाया गया कोई अधिवक्ता संगम तत्पश्चात् उसी प्रकार किसी भी समय मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के लिए विधिज्ञ परिषद् को आवेदन कर सकेगा ।

विधिज्ञ संगमों की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण ।

(2) मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ, संगम के नियम या उप-विधियां, संगम के पदाधिकारियों के नाम और पते तथा संगम के प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, आयु, नामांकन की तारीख और व्यवसाय का सामान्य स्थान दर्शाती हुई संगम के सदस्यों की एक अद्यतन सूची, लगाई जाएगी ।

(3) विधिज्ञ परिषद्, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी यह आवश्यक समझे, संगम को मान्यता दे सकेगी और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में जारी करेगी जैसा विहित किया जाए ।

(4) विधिज्ञ संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

15. (1) प्रत्येक विधिज्ञ संगम, प्रति वर्ष 15 अप्रैल को या उससे पूर्व, उस वर्ष के 31 मार्च को यथा-विद्यमान अपने सदस्यों की एक सूची विधिज्ञ परिषद् और न्यासी समिति को देगा ।

विधिज्ञ संगमों के कर्त्तव्य ।

(2) प्रत्येक विधिज्ञ संगम निम्नलिखित के बारे में विधिज्ञ परिषद् और न्यासी समिति को सूचित करेगा—

(क) इस के पदाधिकारियों या इसकी सदस्यता में कोई परिवर्तन, जिसके अन्तर्गत ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर प्रवेश और पुनः प्रवेश भी है ;

(ख) इसके सदस्यों में से किसी की मृत्यु या व्यवसाय को बन्द करने या व्यवसाय के स्वैच्छिक निलम्बन को उसके घटित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो समय-समय पर विधिज्ञ परिषद् द्वारा अपेक्षित हों ।

(3) प्रत्येक अधिवक्ता संगम और प्रत्येक विधिज्ञ संगम धारा 10 के अधीन, यथास्थिति, विधिज्ञ परिषद् या न्यासी समिति द्वारा इसको दिए गए निदेशों का पालन करेगा ।

16. जहां धारा 15 के अधीन अधिरोपित किन्हीं कर्त्तव्यों के निर्वहन में अधिवक्ता संगम या विधिज्ञ संगम असफल रहेगा या धारा 10 के अधीन दिए गए निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा, वहां विधिज्ञ परिषद् कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा, ऐसे संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगी :

विधिज्ञ संगमों की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

परन्तु किसी अधिवक्ता संगम या विधिज्ञ संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अधिवक्ता संगम या विधिज्ञ संगम को सुनवाई का युक्तियुक्त वसर न दे दिया गया हो।

निधि की
सदस्यता।

17. (1) राज्य के किसी भी न्यायालय, अधिकरण में या प्राधिकारी के समक्ष व्यवसाय करने वाला कोई अधिवक्ता और विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विधिज्ञ संगम या अधिवक्ता संगम का सदस्य होते हुए निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए न्यासी समिति को ऐसे प्ररूप जैसा विहित किया जाए में आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, न्यासी समिति ऐसी जांच करेगी जैसी वह उचित समझे और आवेदक को निधि में प्रवेश देगी या कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को नामन्जूर करेगी :

परन्तु आवेदन को नामन्जूर करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) प्रत्येक आवेदक, आवेदन के साथ, विहित रीति में आवेदन फीस देगा—

- (i) ऐसे आवेदक की दशा में जिसने आवेदन करने की तारीख को दस वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवसाय किया है, एक सौ रुपये; और
- (ii) ऐसे आवेदक की दशा में जिसने आवेदन करने की तारीख को दस या अधिक वर्षों की अवधि के लिए व्यवसाय किया है, दो सौ रुपये :

परन्तु जब आवेदन उप-धारा (2) के अधीन नामन्जूर किया जाए तो आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस का उसे प्रतिदाय किया जाएगा।

(4) निधि का प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 31 मार्च को या उससे पूर्व निम्नलिखित दरों पर निधि में वार्षिक अभिदान संदत्त करेगा, अर्थात् :—

जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष से कम की अवस्थिति है। एक सौ रुपये।
जहां अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष या अधिक की अवस्थिति है। दो सौ रुपये।

(5) निधि का कोई सदस्य, जो किसी वर्ष के लिए वार्षिक अभिदान उस वर्ष के 31 मार्च को या उससे पूर्व संदत्त करने में असफल रहेगा, निधि की सदस्यता से हटाए जाने का दायी होगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाए गए किसी व्यक्ति को हटाए जाने की तारीख से छः मास के भीतर पच्चीस रुपये की पुनः प्रवेश फीस सहित बकाया के संदाय पर, निधि में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

(7) निधि का प्रत्येक सदस्य, निधि की सदस्यता में प्रवेश के समय, उसकी मृत्यु की दशा में, इस अधिनियम के अधीन सदस्य को देय कोई रकम प्राप्त करने का अधिकार अपने आश्रितों में से एक या अधिक को प्रदत्त करते हुए नामनिर्देशन करेगा।

(8) यदि निधि का कोई सदस्य उप-धारा (7) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो, वह नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिनी को देय रकम या भाग विनिर्दिष्ट करेगा।

(9) निधि का सदस्य, किसी भी समय, न्यासी समिति को लिखित नोटिस भेज कर

नामनिर्देशन रद्द कर सकेगा ; परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे नोटिस के साथ एक नया नामनिर्देशन भेजेगा ।

(10) निधि का प्रत्येक सदस्य जिसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26-क के अधीन राज्य नामावली से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया है या जो स्वेच्छा से व्यवसाय निलंबित करता है, ऐसे अनुरोध या निलम्बन से पन्द्रह दिन के भीतर, उस तथ्य को न्यासी समिति को सूचित करेगा और यदि निधि का कोई सदस्य पर्याप्त कारणों के बिना ऐसा करने में असफल रहता है, तो न्यासी समिति, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन उस सदस्य को देय रकम कम कर सकेगी ।

1961 का
25

18. (1) प्रत्येक अधिवक्ता को, जो कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए निधि का सदस्य रहा है, अपना व्यवसाय बन्द करने पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर रकम संदत्त की जाएगी:

व्यवसाय
बन्द करने
पर रकम
का संदाय ।

परन्तु जहां न्यासी समिति का समाधान हो जाता है कि निधि के किसी सदस्य की मृत्यु या किसी स्थायी शारीरिक या मानसिक निःशक्तता के परिणामस्वरूप निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर, व्यवसाय बन्द हो जाता है, तो न्यासी समिति, यथास्थिति, निधि के सदस्य को या उनके नामनिर्देशिनी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर रकम संदत्त कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—वह अवधि, जिसके दौरान निधि का कोई सदस्य निलम्बित रहता है, अविस्थिति के वर्षों की गणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं ली जाएगी ।

(2) जहां निधि के किसी सदस्य की उप-धारा (1) के अधीन देय रकम प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, वहां निधि के मृत सदस्य को देय रकम, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशिनी या वारिस को संदत्त की जाएगी ।

(3) धारा 17 की उप-धारा (5) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाया गया सदस्य और उस धारा की उप-धारा (6) के अधीन निधि में पुनः प्रवेश दिया गया कोई व्यक्ति, निधि की सदस्यता से हटाए जाने की तारीख और पुनः प्रवेश की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, इस अधिनियम के अधीन निधि में से किसी रकम के संदाय का हकदार नहीं होगा ।

(4) कोई सदस्य, जिसे विधिवत परिषद् द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अवचार के लिए निलंबित किया गया है, ऐसे निलम्बन की अवधि के लिए, निधि में से किसी रकम के संदाय के लिए हकदार नहीं होगा ।

1961 का
25

(5) यथास्थिति, प्रत्येक सदस्य या उसका नामनिर्देशिनी अथवा विधिक वारिस निधि में से संदाय के लिए न्यासी समिति को, ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा, जैसा विहित किया जाए ।

19. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निधि में किसी सदस्य का हित या निधि में से कोई रकम प्राप्त करने का निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिनी अथवा विधिक वारिसों का अधिकार समनुद्दिष्ट, अन्यसंक्रामित या प्रभारित नहीं किया जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

निधि में सद-
स्य के हित
के अन्य-
संक्रामण,
कुर्की आदि
पर निर्वन्धन ।

(2) कोई भी लेनदार, निधि या उसमें किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिसों के हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “लेनदार” के अन्तर्गत राज्य या दिवाला से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती या शासकीय रिसीवर है।

सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य फायदे।

20. न्यासी समिति, निधि के सदस्य के कल्याण के लिए—

- (क) निधि के सदस्य की समूह जीवन बीमा पालिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम से अभिप्राप्त कर सकेगी;
- (ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं की ऐसी रीति में जैसी विहित की जाएं व्यवस्था कर सकेगी; और
- (ग) ऐसे अन्य फायदों जैसे विहित किए जाएं की व्यवस्था कर सकेगी।

निधि के सदस्य को अनुग्रहपूर्वक अनुदान।

21. (1) न्यासी समिति इसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और दावे की असलीयत के बारे में समाधान होने के पश्चात् सदस्य को निधि में से निम्नलिखित में अनुग्रहपूर्वक अनुदान कर सकेगी—

- (क) कम से कम एक मास के लिए अस्पताल में रखने की दशा में या जहां शारीरिक शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो; या
- (ख) यदि वह क्षय रोग, कुष्ठ, लकवा, कैंसर, चित्त-विकृति या कुछ अन्य गम्भीर रोगों या निःशक्तताओं से ग्रस्त है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात अनुदान, पांच वर्ष की अवधि के दौरान, दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं होगा।

निर्धन और निःशक्त अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों।

22. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, न्यासी समिति स्वविवेकानुसार भी निर्धन, निःशक्त या अन्य अधिवक्ताओं के कल्याणकारी स्कीमों में संचालित करने के लिए, चाहे वे निधि के सदस्य हैं या नहीं, निधि में से वित्तीय सहायता दे सकेगी।

न्यासी समिति की बैठकें।

23. (1) न्यासी समिति की बैठक तीन कलैन्डर मास में कम से कम एक बार या अधिक बार होगी यदि इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझी जाए।

(2) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यासी समिति के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य, न्यासी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) न्यासी समिति की बैठक के समक्ष आने वाले किसी विषय का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा।

24. न्यासी समिति के गैर-सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के संदाय के हकदार होंगे जो विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों को अनुज्ञेय हैं।

न्यासी समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते।

25. (1) न्यासी समिति के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील विधिज्ञ परिषद् को होगी।

न्यासी समिति के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील।

(2) अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और इसके साथ —

- (क) आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रति; और
- (ख) हिमाचल प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में विधिज्ञ परिषद् के खाते में पच्चीस रुपये के संदाय के सबूत की रसीद, लगाई जाएगी।

(3) अपील, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।

(4) अपील पर विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

26. (1) विधिज्ञ परिषद् "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट" से अन्तर्लिखित पांच रुपये मूल्य की कल्याण निधि टिकट, ऐसे डिजाइन जैसा विहित किया जाए में मुद्रित और वितरित करवाएगी।

विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि टिकटों का मुद्रण और वितरण।

(2) टिकटें 2.54 से 0 मी 0 गुणा 5.08 से 0 मी 0 के आकार की होंगी।

(3) टिकटें विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रहेंगी।

(4) विधिज्ञ परिषद्, टिकटों के वितरण और विक्रय का नियन्त्रण, विधिज्ञ संगमों और अधिवक्ता संगमों के माध्यम से करेगी।

(5) विधिज्ञ परिषद्, विधिज्ञ संगम और अधिवक्ता संगम टिकटों का उचित लेखा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति जैसी विहित की जाए में रखेंगे।

(6) विधिज्ञ संगम और अधिवक्ता संगम, विधिज्ञ परिषद् से टिकटें, आनुषंगिक व्यय लेखे ऐसे मूल्य का दस प्रतिशत कम करके उनका मूल्य संदत्त करने के पश्चात् खरीदेगा।

27. (1) निधि का प्रत्येक सदस्य उस द्वारा दाखिल किए गए प्रत्येक वकालतनामा पर एक टिकट लगाएगा और जब तक इस पर टिकट न लगी हो कोई भी वकालतनामा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष दाखिल नहीं किया जाएगा।

वकालतनामा पर टिकटें लगाना।

(2) टिकटों का मूल्य किसी भी मामले में खर्चा नहीं होगा, न ही किसी मुबकिल से किसी भी दशा में संगृहीत किया जाएगा।

(3) निधि के किसी सदस्य द्वारा उप-धारा (1) और (2) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन उसे, निधि के फायदों से सम्पूर्णतः या भागतः वंचित करेगा और न्यासी समिति ऐसे दृष्टान्तों की रिपोर्ट समुचित कार्रवाई के लिए, विधिज्ञ परिषद् को करेगी।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए वकालत-नामा पर लगाई गई प्रत्येक टिकट, ऐसी रीति जैसी विहित की जाए, में रद्द की जाएगी।

सद्भाव-
पूर्वक की
गई कार्र-
वाई के लिए
संरक्षण।

28. (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात से कारित हुई किसी नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या न्यासी समिति अथवा विधिज्ञ परिषद् के विरुद्ध न होगी।

सिविल न्या-
लयों की
अधिकारिता
का वर्जन।

29. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न को तथ, विनिश्चित या निपटाने अथवा किसी विषय को अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका इस अधिनियम के अधीन या द्वारा न्यासी समिति या विधिज्ञ परिषद् द्वारा तथ, विनिश्चित या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित है।

साक्षियों को
समन करने
और साक्ष्य
लेने की
शक्ति।

30. न्यासी समिति और विधिज्ञ परिषद् को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों के बारे में किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

1908 का 5

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना ;
- (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

नियम बनाने
की शक्ति।

31. विधिज्ञ परिषद्, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

अनुसूची को
संशोधित
करने की
शक्ति।

32. सरकार, न्यासी समिति की सिफारिश पर और निधि में रकम की उपलब्धता का सम्यक् ध्यान रखते हुए अनुसूची में त्रिनिदिष्ट दलों को, अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी।

नियमों और
अधिसूच-
नाओं का
रखा जाना।

33. धारा 31 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 32 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी की जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा पटल पर रखी जाएगी और यदि उस सत्र के या आगामी सत्र के जिसमें उसे रखा गया है अवसान के पूर्व, विधान सभा ऐसे नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है या विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

[धाराएं 9(2) (ङ) और 18 तथा 32 देखिए]

	रुपए
निधि के सदस्य के रूप में 30 वर्ष	90,000
निधि के सदस्य के रूप में 29 वर्ष	87,000
निधि के सदस्य के रूप में 28 वर्ष	84,000
निधि के सदस्य के रूप में 27 वर्ष	81,000
निधि के सदस्य के रूप में 26 वर्ष	78,000
निधि के सदस्य के रूप में 25 वर्ष	75,000
निधि के सदस्य के रूप में 24 वर्ष	72,000
निधि के सदस्य के रूप में 23 वर्ष	69,000
निधि के सदस्य के रूप में 22 वर्ष	66,000
निधि के सदस्य के रूप में 21 वर्ष	63,000
निधि के सदस्य के रूप में 20 वर्ष	60,000
निधि के सदस्य के रूप में 19 वर्ष	57,000
निधि के सदस्य के रूप में 18 वर्ष	54,000
निधि के सदस्य के रूप में 17 वर्ष	51,000
निधि के सदस्य के रूप में 16 वर्ष	48,000
निधि के सदस्य के रूप में 15 वर्ष	45,000
निधि के सदस्य के रूप में 14 वर्ष	42,000
निधि के सदस्य के रूप में 13 वर्ष	39,000
निधि के सदस्य के रूप में 12 वर्ष	36,000
निधि के सदस्य के रूप में 11 वर्ष	33,000
निधि के सदस्य के रूप में 10 वर्ष	30,000
निधि के सदस्य के रूप में 9 वर्ष	27,000
निधि के सदस्य के रूप में 8 वर्ष	24,000
निधि के सदस्य के रूप में 7 वर्ष	21,000
निधि के सदस्य के रूप में 6 वर्ष	18,000
निधि के सदस्य के रूप में 5 वर्ष	15,000
निधि के सदस्य के रूप में 4 वर्ष	12,000
निधि के सदस्य के रूप में 3 वर्ष	9,000
निधि के सदस्य के रूप में 2 वर्ष	6,000
निधि के सदस्य के रूप में 1 वर्ष	3,000

उद्देश्यों और कार्यों का कथन

समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, कल्याणकारी राज्य का सर्वोपरि उद्देश्य है। विधिक व्यवसाय, समाज के वर्गों में से एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए वास्तव में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है और ऐसी सामाजिक सुरक्षा सुगमता से, राजकोष पर किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक बोझ डाले बिना प्रदान की जा सकती है। यद्यपि विधिक व्यवसाय के सदस्य शिखर पर समृद्ध हैं तथापि निम्नस्तर पर भी संघर्षरत हैं। राज्य में सामान्य कोटि का अधिवक्ता केवल संघर्ष और कठिनाई का ही सामना नहीं करता अपितु संकट और गरीबी की स्थिति में, जिसके अन्तर्गत उसका अतामयिक निवन भी है, जीवन निर्वाह के लिए लाचार हो जाता है। इस कठिनाई को, उद्देश्यपूर्ण सामाजिक सुरक्षा विधान द्वारा, कम और हल्का किया जा सकता है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने, जिनमें तामिलनाडू, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा सम्मिलित हैं, अपने-अपने राज्यों में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए विधियाँ अधिनियमित की हैं। हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् ने भी इस राज्य में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए निधि के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। अधिवक्ताओं के लिए कल्याण विधान अधिनियमित करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। इस पृष्ठभूमि में विधि द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि का, जिसका प्रबन्ध कानूनी न्यासी समिति द्वारा किया जाएगा, गठन किया जाना समीचीन है ताकि विधिज्ञ परिषद् द्वारा रखी गई राज्य नामावली से निवृत्ति या मृत्यु या स्थायी शारीरिक या मानसिक निःशक्ता के कारण अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय बन्द करने पर अधिवक्ता का नाम हटाए जाने की दशा में वह या उसका नामनिर्देशित अथवा उसका आश्रित उक्त निधि में से एकमुश्त रकम प्राप्त कर सके। रकम की मात्रा, निधि की सदस्यता की अवधि पर निर्भर होगी। इस उपाय से विधिक व्यवसाय के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

विजय सिंह मनकोटिया,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला, 7 मार्च, 1996

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 31 विधिज्ञ परिषद् को, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने को सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड 32, राज्य सरकार को न्यासी समिति की सिफारिशों और निधि में रकम की उपलब्धता का सम्यक् ध्यान रखते हुए, अधिसूचना द्वारा अनुमूची में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित करने के लिए सशक्त करता है। इस प्रकार बनाए गए नियम और इस प्रकार जारी की गई अधिसूचनाएं विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी। प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 1996.

**THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND
BILL, 1996**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the constitution of a welfare fund for the benefit of advocates on cessation of practice in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Advocate" means a person whose name has been entered in the State roll of advocates prepared and maintained by the Bar Council of Himachal Pradesh State under section 17 of the Advocates Act, 1961 and who is a member of a Bar Association;

(b) "Bar Association" means an association of advocates recognised and registered by the Bar Council under section 14;

(c) "Bar Council" means a Bar Council of Himachal Pradesh constituted under section 3 of the Advocates Act, 1961;

(d) "cessation of practice" means removal of the name of an advocate from the State roll maintained by the Bar Council on account of his death or retirement or on account of his voluntary cessation of practice on the ground of permanent physical or mental disability;

(e) "dependents" means the spouse, parent and children dependent on the member of the Fund and includes his widowed daughter and major children who suffer from physical disability or insanity and who are maintained by him or such of them who survive on his death;

(f) "Fund" means the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund constituted under section 3;

(g) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(h) "Member of the Fund" means an advocate admitted to the benefits of the Fund and continuing to be a member thereof under the provisions of this Act;

25 of 1961

25 of 1961

- (i) "prescribed" means prescribed by the Bar Council by rules made under this Act;
- (j) "retirement" means stoppage of practice as an advocate, communicated and recorded by the Bar Council;
- (k) "Stamp" means the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Stamp printed and distributed under section 26;
- (l) "State" means the State of Himachal Pradesh;
- (m) "suspension of practice" means voluntary suspension of practice as an advocate or suspension by the Bar Council for misconduct;
- (n) "Trustee Committee" means the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Trustee Committee constituted under section 4;
- (o) "Vakalatnama" includes memorandum of appearance or any other document by which an advocate is empowered to appear or plead before any court, tribunal or institution or other authority legally authorised by any law to take evidence or to adjudicate or decide any dispute.

Advocates
Welfare
Fund.

3. (1) The Government shall constitute a Fund called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund.

(2) There shall be credited to the Fund—

- (a) an initial amount of ten thousand rupees or such other higher amount as the Bar Council may credit to this Fund at the time of its constitution;
- (b) the amount paid by the Bar Council under section 13;
- (c) any further contribution that may be made by the Bar Council;
- (d) any voluntary donation or contribution made to the Fund by the Bar Council of India, any Bar Association, any Advocates Association or other association or institution, or any advocate or other person;
- (e) any sum borrowed under section 11;
- (f) all sums collected under section 17;
- (g) all sums received from the Life Insurance Corporation of India on the death of a member of the Fund under a Group Insurance Policy;
- (h) any profit or dividend or refund received from the Life Insurance Corporation of India in respect of policies of Group Insurance of the members of the Fund;
- (i) any interest or dividend or other return on any investment made of any part of the Fund; and
- (j) all sums collected by way of sale of stamps under section 27.

(3) The sums specified in sub-section (2) shall be paid to, or collected by, such agencies, at such intervals and in such manner, and the accounts of the Fund shall be maintained in such manner, as may be prescribed.

Constitution
of Trustee
Committee.

4. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute with effect from such date as may be specified therein a Committee to be called "the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Trustee Committee".

(2) The Trustee Committee shall be a body corporate by the aforesaid name having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to enter into contract and shall by the said name, sue and be sued.

(3) The Trustee Committee shall consist of—

- (a) the Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh who shall be the Chairman of the Trustee Committee, Ex-officio;
- (b) the Advocate General of the State of Himachal Pradesh, Ex-officio Member;
- (c) the Secretary to the Government in Law Department, Ex-officio Member;
- (d) two members nominated by the Government ;
- (e) three members of the Bar Council nominated by it ; and
- (f) the Secretary of the Bar Council who shall be the Secretary of the Trustee Committee, Ex-officio.

(4) A member nominated by the Government under clause (d) and by the Bar Council under clause (e) of sub-section (3) shall hold office for a term of three years or in the case of members mentioned under clause (e) of sub-section (3) upto the duration of his membership in the Bar Council, whichever is less, or till such member resigns his office and his resignation is accepted by the Chairman.

5. (1) A person shall be disqualified for being nominated, under clauses (d) and (e) of sub-section (3) of section 4, for being a member of the Trustee Committee, if he—

- (a) becomes of unsound mind; or
- (b) is adjudged insolvent; or
- (c) is absent without leave of the Trustee Committee for more than three consecutive meetings of the Trustee Committee:

Provided that the member ceasing to hold office under this clause may be allowed to continue as such member by the Trustee Committee, if such member makes an application for the condonation of the absence; or

- (d) is a defaulter to the Fund (in case he is a member of the Fund); or
- (e) is convicted by a criminal court for an offence involving moral turpitude, unless such conviction has been set-aside; or
- (f) being a person nominated by the Bar Council—
 - (i) ceases to practise as an advocate under the Advocates Act, 1961; or
 - (ii) ceases to be member of the Bar Council; or
 - (iii) is debarred from practising on the ground of professional misconduct.

(2) The Government may remove any member who is or has become disqualified under sub-section (1) from the membership of the Trustee Committee:

Disqualification and removal of nominated members of Trustee Committee.

Provided that no order removing any member nominated by the Bar Council shall be passed unless the member and the Bar Council have been given an opportunity of being heard.

Resignation by nominated members of Trustee Committee and filling up of casual vacancies.

6. (1) Any member nominated under clauses (d) and (e) of sub-section (3) of section 4 may resign his office by giving three months notice in writing to the Government or the Bar Council, as the case may be, and on such resignation being accepted by the Government or as the case may be by the Bar Council, he shall be deemed to have vacated his office.

(2) A casual vacancy in the office of a member nominated under clause (d) or clause (e) of sub-section (3) of section 4 occurring on account of death, resignation or removal of a member under sub-section (2) of section 5 may be filled up, as soon as it may be convenient, by nomination of any person as a member thereto by the Government or the Bar Council, as the case may be, and a person so nominated to fill such vacancy shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

Acts of Trustee Committee not to be invalidated by vacancy, defect etc.

7. No act done or no proceeding taken by or under this Act by the Trustee Committee shall be invalidated merely by reason of—

- (a) any vacancy or defect in the constitution of the Committee; or
- (b) any defect or irregularity in the nomination of any person as a member thereof; or
- (c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the merits of the case.

Vesting and application of Fund.

8. The Fund shall vest in, and be held and applied by, the Trustee Committee subject to the provisions, and for the purposes, of this Act.

Functions of Trustee Committee.

9. (1) The Trustee Committee shall administer the Fund.

(2) In the administration of the Fund, the Trustee Committee shall, subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder,—

- (a) hold the amounts and assets belonging to the Fund in trust;
- (b) receive applications for admission or re-admission to the Fund and dispose of such applications within ninety days from the date of receipt thereof;
- (c) receive applications from the members of the Fund, their nominees or legal heirs, as the case may be, for payment out of the Fund, and conduct such enquiry as it deems necessary for the disposal of such applications and dispose of the applications within ninety days from the date of receipt thereof;
- (d) record in the minutes book of the Trustee Committee, its decisions on the applications;
- (e) pay to the applicants amounts at the rates specified in the Schedule;
- (f) send such periodicals and annual reports, as may be prescribed, to the Government and the Bar Council;
- (g) communicate to the applicants, by post under certificate of posting, the decisions of the Trustee Committee in respect of

applications for admission or re-admission to the Fund or claims to the benefit of the Fund;

- (h) appoint such officers and servants as it may think necessary for carrying out the purposes of this Act on such terms and conditions as may be prescribed; and
- (i) do such other acts as are, or may be, required to be done by it under this Act and the rules made thereunder.

10. The Bar Council or the Trustee Committee may give to the Advocates Association or Bar Association such directions as, in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act.

Power to give directions.

11. (1) The Trustee Committee may, with the prior approval of the Government and the Bar Council, borrow, from time to time, any sum required for carrying out the purposes of this Act,

Funds, borrowing and investment.

(2) The Trustee Committee shall deposit all moneys and receipts forming part of the Fund in any Scheduled Bank or invest the same in any units issued by the Unit Trust of India or in any National Savings Certificates issued by any Post Office or in loans floated by any Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government or in securities or in loans floated by the Central Government or the State Government or in any other manner as the Bar Council may, from time to time, direct with the prior approval of the Government.

(3) All amounts due and payable under this Act and all expenditure related to the management and administration of the Fund shall be paid out of the Fund.

(4) The accounts of the Trustee Committee shall be audited annually by a Chartered Accountant approved by the Bar Council.

(5) The accounts of the Trustee Committee as certified by the auditor, together with the audit report thereon, shall be forwarded to the Bar Council and the Government by the Trustee Committee and the Bar Council may issue such directions as it deems fit to the Trustee Committee in respect thereof.

(6) The Trustee Committee shall comply with the directions issued by the Bar Council under sub-section (5).

12. The Secretary of the Trustee Committee shall—

Powers and duties of Secretary.

- (a) be the chief executive authority of Trustee Committee and responsible for carrying out its decisions;
- (b) represent the Trustee Committee in all suits and proceedings for and against the Trustee Committee;
- (c) authenticate by his signature all decisions and instructions of the Trustee Committee;
- (d) operate the bank accounts of the Trustee Committee jointly with the Chairman or his nominee;
- (e) convene meetings of the Trustee Committee and prepare its minutes;

- (f) attend the meeting of the Trustee Committee with all the necessary records and information;
- (g) maintain such forms, registers and other records as may be prescribed from time to time and do all correspondence relating to the Trustee Committee;
- (h) prepare an annual statement of business transacted by the Trustee Committee during each financial year;
- (i) inspect and verify periodically the accounts and registers of the Bar Associations regarding the sale of stamps and other matters connected therewith; and
- (j) do such other acts as may be directed by the Trustee Committee and the Bar Council.

Transfer of
certain mo-
ne to the
Fund.

13. The Bar Council shall pay to the Fund annually an amount equal to ten per cent of the enrolment fees realised by it.

Recognition
and regis-
tration of
Bar Asso-
ciations.

14. (1) All associations of advocates known by any name, functioning in any part of the State may, before a date to be notified or before such extended date as may be notified by the Bar Council in this behalf, apply to the Bar Council in such form and manner as may be prescribed for recognition and registration. Any association of advocates formed after the date of commencement of this Act may at any time thereafter likewise apply to the Bar Council for recognition and registration.

(2) Every application for recognition and registration shall be accompanied by the rules or bye-laws of the association, names and addresses of the office-bearers of the association and an upto-date list of the members of the association showing the name, address, age, date of enrolment and the ordinary place of practice of each member.

(3) The Bar Council may, after such enquiry as it deems necessary, recognise the association and issue a certificate of registration in such form as may be prescribed.

(4) The decision of the Bar Council regarding the recognition and registration of a Bar Association shall be final.

Duties of
Bar Asso-
ciations.

15. (1) Every Bar Association shall on or before the 15th April of every year, furnish to the Bar Council and the Trustee Committee a list of its members as on the 31st March of that year.

(2) Every Bar Association shall inform the Bar Council and Trustee Committee of—

- (a) any change in its office-bearers or in its membership, including admissions and re-admissions, within thirty days of such change;
- (b) the death or other cessation of practice or voluntary suspension of practice of any of its members within thirty days from the date of occurrence thereof; and
- (c) such other matters as may be required by the Bar Council from time to time.

(3) Every Advocates Association and every Bar Association shall carry out the directions given to it under section 10 by the Bar Council or the Trustee Committee, as the case may be.

16. Where the Advocates Association or the Bar Association fails to discharge any of the duties imposed under section 15, or fails to carry out the directions given under section 10, the Bar Council may, for reasons to be recorded by order, cancel the recognition and registration of such Association:

Cancellation of recognition and registration of Bar Association.

Provided that no order cancelling the recognition and registration of any Advocates Association or Bar Association shall be passed unless the Advocates Association or the Bar Association has been given a reasonable opportunity of being heard.

17. (1) Any advocate practising in or before any court, tribunal or authority in the State and being a member of a Bar Association or an Advocates Association recognised by the Bar Council may apply to the Trustee Committee for admission as a member of the Fund in such form as may be prescribed.

Membership of the Fund.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Trustee Committee shall make enquiry as it deems fit and either admit the applicant to the Fund or, for reasons to be recorded in writing, reject the application:

Provided that no order rejecting an application shall be passed unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(3) Every applicant shall, alongwith the application, pay, in the prescribed manner, an application fee—

(i) in the case of an applicant who, on the date of application has practised for a period of less than ten years, rupees one hundred; and

(ii) in the case of an applicant who, on the date of application has practised for a period of ten years or more, rupees two hundred:

Provided that when an application is rejected under sub-section (2) the application fee paid by the applicant shall be refunded to him.

(4) Every member of the Fund shall pay an annual subscription to the Fund on or before the 31st March of every year at the following rates, namely :—

Where the standing of the advocate at the Bar is less than ten years.	one hundred rupees
---	--------------------

Where the standing of the advocate at the Bar is ten years or more. two hundred rupees.

(5) Any member of the Fund who fails to pay the annual subscription for any year on or before the 31st March of that year shall be liable to be removed from the membership of the Fund.

(6) A person removed from the membership of the Fund under sub-section (5) may be re-admitted to the Fund on payment of the arrears with the readmission fee of twenty five rupees within six months from the date of removal.

(7) Every member of the Fund shall, at the time of admission to the membership of the Fund, make nomination conferring on one or more of his dependents the right to receive, in the event of his death, any amount payable to the member under this Act.

(8) If a member of the Fund nominates more than one person under sub-section (7), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees.

(9) A member of the Fund, may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Trustee Committee; provided that he shall, along with such notice, send a fresh nomination.

(10) Every member of the Fund who has requested the removal of his name from the State roll under section 26-A of the Advocates Act, 1961 or who voluntarily suspends practice shall within fifteen days of such request or suspension, intimate that fact to the Trustee Committee and if any member of the Fund fails to do so without sufficient reasons, the Trustee Committee may reduce, in accordance with such principles as may be prescribed, the amount payable to that member under this Act.

25 of 1961

Payment of amount on cessation of practice.

18. (1) Every advocate who has been a member of the Fund for a period of not less than ten years shall, on his cessation of practice, be paid an amount at the rate specified in the Schedule :

Provided that where the Trustee Committee is satisfied that a member of the Fund ceases to practise within a period of ten years from the date of his admission as member of the Fund as a result of his death or of any permanent physical or mental disability, the Trustee Committee may pay the member of the Fund or his nominee, as the case may be, an amount at the rate specified in the Schedule.

Explanation.—The period during which the member of the Fund remained suspended shall not be considered for the purpose of counting the year of standing.

(2) Where a member of the Fund dies, before receiving the amount payable under sub-section (1), his nominee or legal heir, as the case may be, shall be paid the amount payable to the deceased member of the Fund.

(3) Any person removed from the membership of the Fund under sub-section (5) of section 17 and re-admitted to the Fund under sub-section (6) of that section shall not be entitled to payment of any amount from the Fund under this Act during the period between the date of his removal from the membership of the Fund and the date of readmission.

(4) Any member who is suspended by the Bar Council for misconduct under the Advocates Act, 1961 shall not be entitled to payment of any amount from the Fund under this Act for the period of such suspension.

(5) Every member or his nominee or legal heir, as the case may be, shall apply for payment out of the Fund to the Trustee Committee, in such form, as may be prescribed.

19. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the interest of any member in the Fund, or the right of a member of the Fund or his nominee or legal heirs to receive any amount from the Fund, shall not be assigned, alienated or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court, tribunal or other authority.

Restriction on alienation, attachment etc. of interest of members in the Fund.

(2) No creditor shall be entitled to proceed against the Fund or the interest therein of any member or his nominee or legal heirs.

Explanation.—For the purpose of this section, “creditor” includes the State, or an Official Assignee or Official Receiver appointed under the law relating to insolvency for the time being in force.

20. The Trustee Committee may, for the welfare of the members of the Fund—

Group Life Insurance for members and other benefits.

(a) obtain from the Life Insurance Corporation of India, policies of Group Insurance for the members of the Fund ;

(b) provide in such manner as may be prescribed for medical and educational facilities for the members of the Fund and their dependents; and

(c) provide for such other benefits as may be prescribed.

21. (1) The Trustee Committee on an application submitted to it, and after being satisfied about the genuineness of the claim, may allow *ex-gratia* grant to a member from the Fund—

Ex-gratia grant to a member of the Fund.

(a) in the case of hospitalisation at least for one month or involving a major physical operation; or

(b) if he is suffering from tuberculosis, leprosy, paralysis, cancer, unsoundness of mind or from some other serious diseases or disabilities.

(2) The grant so allowed under sub-section (1) shall not exceed a sum of ten thousand rupees during a period of five years.

Welfare
scheme for
indigent and
disabled
advocates.

22. Notwithstanding anything contained in this Act, the Trustee Committee may also at its discretion give financial assistance from the Fund to organise welfare schemes for the indigent, disabled or other advocates, who may or may not be members of the Fund.

Meetings of
Trustee
Committee.

23. (1) The Trustee Committee shall meet at least once in three calendar months or more often if found necessary to transact business under this Act and the rules made thereunder.

(2) One third members of the Trustee Committee shall form the quorum for a meeting of the Committee.

(3) The Chairman or, in his absence, a member elected from amongst the members present, shall preside over the meeting of the Trustee Committee.

(4) Any matter coming up before a meeting of the Trustee Committee shall be decided by a majority of the members present and voting at the meeting and in the case of an equality of votes, the Chairman or the member presiding over the meeting shall have a casting vote.

Travelling
and daily
allowances
to members
of Trustee
Committee.

24. The non-official members of the Trustee Committee shall be entitled to be paid such travelling allowance and daily allowance as are admissible to the members of the Bar Council.

Appeal ag-
ainst deci-
sions of
Trustee
Committee.

25. (1) Appeal against any decision of the Trustee Committee shall lie to the Bar Council.

(2) The appeal shall be in the prescribed form and shall be accompanied by—

(a) a copy of the order appealed against; and

(b) a receipt evidencing payment of twenty-five rupees to the credit of the Bar Council in any of the branches of the State Bank of India in Himachal Pradesh.

(3) The appeal shall be filed within thirty days from the date of receipt of the order appealed against.

(4) The decision of the Bar Council on the appeal shall be final.

Printing and
distribution
of Advo-
cates Wel-
fare Fund
Stamps
by Bar
Council.

26. (1) The Bar Council shall cause to be printed and distributed Welfare Fund Stamps of the value of five rupees inscribed "Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Stamps" in such design as may be prescribed.

(2) The stamps shall be of the size 2.54 cm. by 5.08 cm.

(3) The custody of the stamps shall be with the Bar Council.

(4) The Bar Council shall control the distribution and sale of the stamps through the Bar Associations and Advocates Associations.

(5) The Bar Council, the Bar Associations and Advocates Associations shall keep proper accounts of the stamps in such form and in such manner as may be prescribed.

(6) The Bar Associations and Advocates Associations shall purchase the stamps from the Bar Council after paying the value thereof less ten per cent of such value towards incidental expenses.

27. (1) Every member of the Fund shall affix one stamp on every vakalatnama filed by him and no vakalatnama shall be filed before any court, tribunal or authority unless it is so stamped. Vakalatnama to bear stamps.

(2) The value of the stamps shall neither be costs in a case nor be collected in any event from the client.

(3) Any contravention of the provisions of sub-sections (1) and (2) by any member of the Fund shall disentitle him, either in whole or in part, to the benefits of the Fund and the Trustee Committee shall report such instances to the Bar Council for appropriate action.

(4) Every stamp affixed on vakalatnama filed before any court, tribunal or other authority shall be cancelled in such manner as may be prescribed.

28. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder. Protection of action taken in good faith.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government or the Trustee Committee or the Bar Council for any damage caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

29. No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with or to be determined by the Trustee Committee or the Bar Council. Bar of jurisdiction of civil courts

30. The Trustee Committee and the Bar Council shall, for the purpose of any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:— Power to summon witnesses and take evidence.

(a) enforcing the attendance of any person or examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of documents ;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commission for the examination of witnesses.

31. The Bar Council may, with the previous approval of the Government, by notification, make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act. Power to make rules

32. The Government may, by notification, on the recommendation of the Trustee Committee and having due regard to the availability of the amount in the Fund, amend the rates specified in the Schedule. Power to amend Schedule.

Laying of
rules and
notifications.

33. Every rule made under section 31, and every notification issued under section 32, shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid on the Table of the Legislative Assembly and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the next session, the Assembly makes any modification in any such rule or notification or the Assembly decides that rule or the notification should not be made or issued, the rule or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification.

THE SCHEDULE

[See sections 9 (2) (e) and 18 and 32]

	Rs.
30 years as a member of the Fund	90,000
29 years as a member of the Fund	87,000
28 years as a member of the Fund	84,000
27 years as a member of the Fund	81,000
26 years as a member of the Fund	78,000
25 years as a member of the Fund	75,000
24 years as a member of the Fund	72,000
23 years as a member of the Fund	69,000
22 years as a member of the Fund	66,000
21 years as a member of the Fund	63,000
20 years as a member of the Fund	60,000
19 years as a member of the Fund	57,000
18 years as a member of the Fund	54,000
17 years as a member of the Fund	51,000
16 years as a member of the Fund	48,000
15 years as a member of the Fund	45,000
14 years as a member of the Fund	42,000
13 years as a member of the Fund	39,000
12 years as a member of the Fund	36,000
11 years as a member of the Fund	33,000
10 years as a member of the Fund	30,000
9 years as a member of the Fund	27,000
8 years as a member of the Fund	24,000
7 years as a member of the Fund	21,000
6 years as a member of the Fund	18,000
5 years as a member of the Fund	15,000
4 years as a member of the Fund	12,000
3 years as a member of the Fund	9,000
2 years as a member of the Fund	6,000
1 year as a member of the Fund	3,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Social security to different sections of the society is one of the paramount objective of a welfare State. Legal profession is one of the sections of the society, which indeed requires social security and such social security can be provided to the legal profession without any burden to the State Exchequer. The members of the legal profession though affluent at top nevertheless struggle at the lower rung. Average lawyer in the State not only struggles and faces hardship but also has nothing to look forward to in the case of distress and adversity including untimely death. The rigorous of the hardship can be reduced and softened with a purposeful social security legislation.

Various State Governments including Tamil Nadu, Rajasthan, Kerala, Maharashtra, Gujrat and Orissa have enacted laws for the promotion of welfare of the advocates practising in their respective States. The Bar Council of Himachal Pradesh also represented to the State Government for the constitution of a Fund for the promotion of the welfare of the Advocates practising in Himachal Pradesh. The question of enacting welfare legislation for the Advocates has been under consideration of the State Government for some-time past. In this background, it is felt expedient to constitute, by law, an Advocates Welfare Fund to be managed by a statutory Trustee Committee, so that in the event of removal of the name of an Advocate from the State roll, maintained by the Bar Council of Himachal Pradesh, on cessation of practice an Advocate on account of his retirement or death, permanent physical or mental disability he or his nominees or dependants may be paid a lump-sum, amount from that Fund. The quantum of amount shall depend on the period of membership of the Fund.

This measure will go a long way in providing social security to the members of the legal profession.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIJAI SINGH MANKOTIA,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The 7th March, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

NIL

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 31 of the Bill empowers the Bar Council, with the previous approval of the Government, to make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act. Clause 32 of the Bill empowers the State Government, by notification, on the recommendation of the Trustee Committee and having due regard to the availability of the amount in the Fund, amend the rates specified in the Schedule. The rules so made and notifications so issued are to be laid before the State Legislative Assembly. The proposed delegations are essential and normal in character.